प्रेषक.

एम0एच0 खान, प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में, निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक : 20 जनवरी, 2014

विषयः वाह्य सहायतित परियोजनाओं के अन्तर्गत ट्रान्य-1 हेतु स्वीकृत कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्यांश की घनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्य्क्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सैक्टर डेवलपमेन्ट इनवेस्टमेन्ट प्रोग्राम, देहरादून के पत्र संख्याः यू.यू.एस.डी.आई.पी. / F&A-07/1014, दिनांक 19.09.2013 के प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यू०यू०एस०डी०आई०पी० के अन्तर्गत ट्रान्य−1 हेतु स्वीकृत कार्यों के लिए राज्यांश की धनराशि ₹1000.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं.—

 उपरोक्त ट्रान्य-1 के कार्यों हेतु स्वीकृत की जा रही राज्यांश की धनराशि निर्धारित राज्यांश से अधिक होने की दशा में इसकी प्रतिपूर्ति ए०डी०बी० के माध्यम से यथाशीघ्र करा ली जाय।

(II) उक्त धनराशि < 1000.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) की धनराशि आपके द्वारा आहरित कर कार्यकम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बैन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्मेंट प्रोग्राम, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाएगा, जो ऋण अनुबन्ध / परियोजना अनुबन्ध के क्रम में विषयान्तर्गत वर्णित कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत है तथा जिनके सम्बन्ध में नियमानुसार अधिप्राप्ति कार्यवाही की गयी है।

(iv) व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुवल, अधिप्राप्ति नियमावली तथा मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश, अन्य तद्विषयक नियमों एवं समय-समय पर निर्गत तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

(v) उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा।

(vi) अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(vii) मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—2047/XIV-219/2006, दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

(viii) निर्माण एजेन्सी के चयन में शासनादेश संख्या—452/xxvii(1)/2005, दिनांक 05 अप्रैल, 2005 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(ix) पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।



निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

आयुक्त, गढ़वाल / कुमायूं मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।

कार्यकम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्मेंट प्रोग्राम, देहरादून। 6-

मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून। 7-

वित्त अनुभाग-2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन। 8-

समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन। 9-

निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नगर 10-विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करने का कष्ट करें।

बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून। 11-

गार्ड फाइल। 12-

> (अरविन्द सिंह पांगती) अनु सचिव।